

recommended by the NDC Committee on Power;

(b) if so, the extent of additional power generating capacity to be raised in different sectors like hydel, thermal etc. and the estimated cost thereof, indicating region/state-wise break-up; and

(c) estimated demand and targets fixed for the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) The Ninth Five Year Plan (1997-2002) for power sector is under finalisation in Planning Commission.

विद्युत क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश पर 16% लाभ की प्राप्ति

1351. श्री राम जेटमलानी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली उद्योग में निजी क्षेत्र को आकृष्ट करने के लिए निवेशकों को पूंजीनिवेश का 16% लाभंश कमाने की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार बिजली उद्योग में बिजली उत्पादन, परिवहन और वितरण व्यवस्था में 16% लाभंश कमाने को मंजूरी देने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि इस सिद्धांत को स्वीकारने के पश्चात् देश में बिजली की कीमतों में वृद्धि होगी और हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं कर पाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगिन्द्र कुमार भगत राम अलख): (क) निजी विद्युत नीति विद्युत क्षेत्र में निवेशकों के लिए किसी प्रकार के लाभंश के अनुमान की गारंटी प्रदान नहीं करती, क्योंकि शेयर धरकों के लिए लाभंश की घोषणा विद्युत उत्पादक कंपनी करता है, तथापि 30.3.1992 की समय-समय पर यथा संशोधित टैरिफ अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ नियामक प्रचालन सर्वे अर्थात् निर्मित क्षमता

दशाओं पर संबंधित राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ को स्थाई लागत के एक भाग के रूप में विद्युत उत्पादन यूनिट से संबंधित इक्विटी पर 16 प्रतिशत प्रतिफल का प्रावधान किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Loopholes in Energy Management

1352. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to overcome the energy crisis Government had set up a working Group in 1994 to identify loopholes in the energy management in the country;

(b) if so, what are the recommendations of the Working Group;

(c) whether Government propose to introduce a legislation on the basis of the recommendation of the working group; and

(d) if so, what are the salient features of the legislation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) In January, 1994, the Ministry of Power had constituted a Working Group consisting of representatives from Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Power, Coal, Petroleum and Natural Gas, Non-Conventional Energy Sources and Law for formulation of suitable proposals for a selective legislation on Energy Conservation. The Working Group had looked at the various strategies needed to promote energy conservation and concluded that it would be advantageous to meet the desired objectives through a separate legislation.

(c) and (d) The recommendations of the Working Group have been examined